संख्या-440/2020/2276/22-2-2019-17(983)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 15 अक्टूबर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24539/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-02.07.2019) दिनांक-08.08.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता, मो0 ग्यासपुर, थाना-बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बंदी ने दिनांक 24.02.2004 को दोपहर लगभग 3:00 बजे अगरबत्ती की पैकिंग के पैसे लेने आयी लड़की के साथ बलात्कार किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-448/2004 में भा0द0वि0 की धारा-376 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.05.2019 तक 15 वर्ष 02 माह **07** दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 08 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत व जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया है, दोनों पक्षों में विवाद विद्यमान है, बन्दी की समयपूर्व रिहाई से कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 24.02.2004 को अगरबत्ती की पैकिंग के पैसे लेने आयी लड़की के साथ बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजेश कुमार गुप्ता (बन्दी संख्या-40919) पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-440/2020/2276(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-440/2020/2276/22-2-2019-17(983)/2019

दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता, (बन्दी संख्या-40919) मो0 ग्यासपुर, थाना-बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बंदी ने दिनांक 24.02.2004 को दोपहर लगभग 3:00 बजे अगरबत्ती की पैकिंग के पैसे लेने आयी लड़की के साथ बलात्कार किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-448/2004 में भा0द0वि0 की धारा-376 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.05.2019 तक 15 वर्ष 02 माह **07** दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 08 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत व जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया है, दोनों पक्षों में विवाद विद्यमान है, बन्दी की समयपूर्व रिहाई से कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 24.02.2004 को अगरबत्ती की पैकिंग के पैसे लेने आयी लड़की के साथ बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।